an>

Title: Regarding Government Business during the week commencing the 14th December, 2015.

HON. SPEAKER: Now submissions by Members. Shri Subhash Chandra Baheria.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदया, 14.12.2015 को शुरू होने वाले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय चर्चा के लिए जोड़े जाएं :-

1. भीलवाड़ा शहर की चंबल पेयजल योजना के लिए वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने बाबत।

2. राजस्थान के किशनगढ़ से नसीराबाद-भीलवाड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के संबंध में।

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Kodikunnil Suresh.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shrimati Ranjeet Ranjan.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Rattan Lal Kataria.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. Shashi tharoor.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Shailesh Kumar.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary.

...(*Interruptions*)

*__श्री पी.पी.चौधरी (पाली) :__ महोदया, कृपया निम्न अति महत्वपूर्ण विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करने की कृपा करें:-

1. राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में बनी नई ग्राम पंचायतों में मूलभूत विकास के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने के संबंध में।

2. पश्चिमी राजस्थान के गोडावण सर्किट के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय से बजट आवंटित करने के संबंध में।

HON. SPEAKER: Dr. Kirit Somaiya.

...(*Interruptions*)

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Respected Speaker Madam, I request you to include the following issues for discussion in the List of Business for next week....(*Interruptions*)

1. Debate on climate change, the recent incident of Chennai rain and flood. On the background of the Global Environment Conference held at Paris, efforts by world, India's position, awareness and measures to be taken in India. ...(*Interruptions*)
2. Discussion no Multi State Cooperative Credit Societies (MSCS). 2000 MSCS have registered/ being registered without due diligence resulting in increasing non-transparency and fraud since 2008. It is observed that due to lacunae of proper regulatory system the MSCS platform is abused by the ponzi companies and for money laundering. Need to strengthen the regulatory network and stop the abuse. ...(*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): महोदया, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह के कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

(1) पूरे देश में 70 प्रतिशत असंगठित मजदूर हैं जिनकी स्थिति काफी खराब है। इनकी लाचार स्थिति को देखते हुए असंगठित को पांच हजार रुपये सरकारी पेंशन देने हेतु सख्त विधि बनाये जाने के संबंध में। ...(व्यवधान)

(2) आज पूरे देश में कृषि एवं किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। प्रत्येक साल कहीं बाढ़ एवं कहीं सुखाड़ में फसल बर्बाद हो जाता है। जिसके फलस्वरूप हजारों की संख्या में प्रत्येक साल किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है। इसे रोकने हेतु कृषि को उद्योग का दर्जा के साथ-साथ किसान पेंशन एवं फसील बीमा लागू कराने हेतु सख्त नियम बनाए जाने के संबंध में। ...(व्यवधान)

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद) : महोदया, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह के कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

(1) उस्मानाबाद संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना अति आवश्यक है, यहां के केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को सोलापुर जाना पड़ता है तथा उमरगा/उस्मानाबाद में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए। ...(व्यवधान)

(2) प्रधानमंत्री राहत कोष से गरीबों को अधिकतम तीन या साढ़े तीन लाख राशि मंजूर की जाती है, जबकि कई बीमारियों में 8-10 लाख से अधिक की आवश्यकता होती है जो गरीबों द्वारा वहन करने वाली राशि नहीं है तथा इस दायरे को बढ़ाकर कम से कम 8 से 10 लाख तक की जाए। ...(व्यवधान)

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): Madam, our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi has raised the issues of climate change and terrorism at various international platforms during his foreign visits....(*Interruptions*)

Both the issues of terrorism and climate change are becoming important issues for world peace and public health. Therefore, I would request that both the issues may be included in the next business of Lok Sabha which is due for the next week. â€¦ (*Interruptions*)

For my second submission, I would like to request the hon. Petroleum and Natural Gas Minister to include the issue of formation of new policy for auction of oil gas and gas block during the ongoing financial year in order to make new bidding round more progressive, more transparent and market friendly. This issue may be included in the business of Lok Sabha. ...(*Interruptions*)